ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

04/07/2023

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

New Patliputra Colony, Road No. 4A, Near Tennis Court, Patna-13

द हिंदू 04-07-2023 राष्ट्रीय

अजित पवार द्वारा पार्टी और चुनाव चिह्न पर दावा किए जाने पर एनसीपी ने दोपहर का भोजन किया

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नौ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका प्राप्त होने की पुष्टि की; और दुख की बात है कि वह अजित पवार के नेतृत्व में नई राकांपा का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या से अवगत थे।

शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को निष्कासित करने की घोषणा की। शरद पवार ने "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के लिए प्रफुल्ल पटेल और एमएलए सुनील तटकरे को निष्कासित करने की घोषणा की।

शरद पवार ग्रुप	अजित पवार ग्रुप
शरद पवार, जीतेन्द्र आव्हाड, जयन्त पाटिल, सुप्रिया सेल	अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तट करे आदि।

अजित पवार ने कहा कि वह जयंत पाटिल की जगह श्री तटकरे को राज्य3 पार्टी प्रमुख के रूप में नियुक्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए शी, पुतिन, शरीफ की वर्चुअल मेजबानी करेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, मध्य एशियाई राष्ट्रपति फंड एससीओ-काउंसिल ऑफ स्टेट्स के प्रमुखों की 'वर्चुअली मेजबानी' करेंगे (एससीओ-सीएचएस) "नई दिल्ली घोषणा" और दो कट्टरवाद और डिजिटल परिवर्तन का मुकाबला करने पर संयुक्त वक्तव्य; नान आर्थिक सहयोग पहल पर एक समझौते पर बातचीत चल रही है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सभी देश, विशेष रूप से। भारत इस पर हस्ताक्षर करेगा.

ईरान को इस बार एससीओ का नया सदस्य बनाए जाने की उम्मीद है जबकि बेलारूस को अगली बार से नए सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।

इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनाने के पीछे की वजह

हालांकि एससीओ की बैठक व्यक्तिगत बैठक होने वाली थी, लेकिन बाद में भारत ने घोषणा की कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।

संभावित कारणों में से कुछ राष्ट्रपति पुतिन, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शाहबाज शरीफ और चीनी प्रधान मंत्री शी जिनपिंग की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता हैं।

दो साल से लंबित, अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को याचिका दायर करेगा।

अनुसूचित जाति। 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के कदम को चुनौती देने वाली दो साल से लंबित याचिका पर संविधान पीठ 11 जुलाई को सुनवाई करेगी।

लेख को विशेष अधिकार और पूर्वावलोकन प्रदान किया गया है

सरकार ने अनुच्छेद 35ए के तहत 370 को हटा दिया था।

351 ए - राज्यों के विभाजन आदि जैसे मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी और राज्य की विधानमंडल के पास नहीं होगी।

याचिका में कहा गया है कि - अनुच्छेद 370 को रद्द करते समय और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते समय संसद से परामर्श नहीं किया गया।
सरकार ने 2019 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।
अनुच्छेद 370 - जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य दिया गया, जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार और विधानसभा को विशेष अधिकार प्राप्त थे।
दूसरे राज्य का कोई भी भारतीय न तो अपनी ज़मीन छीन सकता था और न ही उस पर कब्ज़ा कर सकता था।
इन सरकार को निरस्त करना। जम्मू-कश्मीर के लिए निवेश, निपटान और आर्थिक प्रगति की खुली खिड़की।

भारतीय रिफाइनरों ने रूसी तेल के लिए युआन में भुगतान करने की बात कही।

भारतीय रिफाइनर्स ने रूस से कुछ तेल आयात के लिए चीनी युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया है, इससे पहले IOCL जैसी भारतीय तेल कंपनियों ने भी दिरहान (यूएई) में भुगतान किया था।
अमेरिकी डॉलर लंबे समय से इनके लिए मुख्य मुद्रा रहा है। व्यापार लेकिन रूस पर प्रतिबंध के बाद रूस डॉलर में भुगतान नहीं लेता है.

केंद्र बंगाल पंचायत चुनाव के लिए अतिरिक्त सशस्त्र बल तैनात करने पर सहमत।

गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ-साथ राज्य सशस्त्र बलों की अतिरिक्त 485 कंपनियों को तैनात करने पर सहमति व्यक्त की है।
राज्य में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होने हैं।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ की 337 कंपनियों की तैनाती का निर्देश दिया था, इस प्रकार मतदान के दिन राज्य में केंद्रीय बलों की कुल 822 कंपनियां तैनात की जाएंगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवीय भूल के कारण बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई, और इसका दोष सिग्नल विभाग पर मढ़ा गया है।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर सौंपी अपनी 40 पेज की रिपोर्ट में बताया है कि 21 जून को बालासोर ट्रेन की टक्कर के कारण सिग्नल और टेलीकम्यूनिकेशन में कई स्तर की गड़बड़ी हुई, जिसमें 191 लोगों की मौत हो गई और 900 से अधिक घायल।
प्राथमिक ज़िम्मेदारी सिग्नल और दूरसंचार (एस एंड टी) विभाग पर डाली गई है और उत्तर सिग्नल गूमटी (बाहंगा बरार) स्टेशन द्वारा किए गए सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में "मानवीय त्रुटि" के कारण दुर्घटना हुई। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि "तोड़फोड़" का कोण ये था या नहीं।
रेलवे द्वारा उठाए गए कदम
सिग्नलिंग वायरिंग आरेख और अन्य दस्तावेजों को पूरा करने और साइट पर सिग्नलिंग सर्किट के अक्षरों को अपडेट करने के लिए ड्राइव करें।
सिग्नलिंग दवा कार्य को पूरा करने के लिए मानक अभ्यास का पालन किया जाना चाहिए।
सिग्नलिंग संशोधन कार्य करने के लिए मानक अभ्यास का पालन किया जाना चाहिए।
परिवर्तन सर्किट के तहत मौजूदा सर्किट का कार्यात्मक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि वास्तविक सर्किट पूर्ण चित्रों के अनुसार है।
सिग्नलिंग सर्किट पर कोई भी ध्यान एक अनुमोदित सर्किट आरेख के साथ और एक अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।
दक्षता और सिग्नलिंग के लिए एक स्पेट टीम तैनात की जानी चाहिए।

आद्रा मालगाड़ी दुर्घटना के बाद दो लोको पायलटों को सेवा से हटा दिया गया।

25 जून को पश्चिम बंगाल के आद्रा रेलवे स्टेशन के पास दो मालगाड़ियों की टक्कर हो गई थी. यह टक्कर सिग्नल पार करने के कारण हुई।

गठित एक जांच समिति ने पाया कि आने वाली ट्रेनों के लोकोपायलट "माइक्रो स्लिप" स्थिति में थे, और इसलिए सिग्नल पार करने के बाद ट्रेन को नियंत्रित नहीं कर सके;

इसके बाद दोनों लोको पायलटों को सेवा से हटा दिया गया है।

केंद्र ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए योजना की घोषणा की

केंद्र सरकार ने यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप गर्भधारण के मामलों में पीड़िता को चिकित्सा, वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) द्वारा घोषित योजना, निर्भया फंड के तत्वावधान में संचालित होगी, जिसमें 74% करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

“हमने नाबालिग पीड़ितों को इस सहायता को साकार करने के लिए राज्य सरकारों और बाल संस्थान (सीसीआई) के सहयोग से मिशन वात्सलय की प्रशासनिक संरचना का भी लाभ उठाया है।

2021 में, MCRB ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत 51,6863 मामले दर्ज किए,

दुनिया

इज़राइल ने पश्चिमी तट को ड्रोन और सैनिकों से निशाना बनाया जिसमें आठ फ़िलिस्तीनी मारे गए।

सोमवार को इज़राइल ने वेस्ट बैंक में मुख्य रूप से जेनिव में कई साइटों पर ड्रोन हमले किए। इससे फिलिस्तीनी की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए, जिनमें से 1 गंभीर रूप से घायल हो गया।

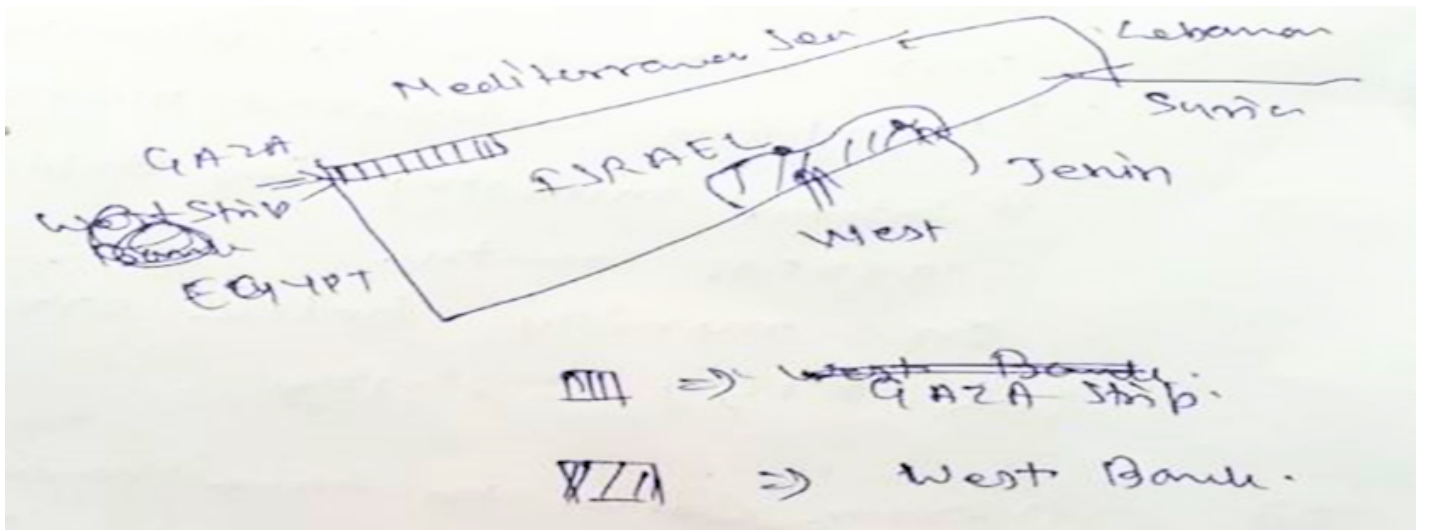

जेनिन शरणार्थी शिविर के अंदर सैकड़ों सैनिक मौजूद रहे, यह सबसे लक्षित ऑपरेशनों में से एक था।

वेस्ट बैंक ISRAE और पाकिस्तानी बस्ती के बीच बंटा हुआ है, जिसमें ज्यादातर फिलिस्तीन है।

गिरफ़्तारी कम होने पर फ्रांस में मेयरों ने दंगा विरोधी रैलियाँ निकालीं

प्रदर्शन - जिसे "गणतंत्र व्यवस्था की वापसी के लिए नागरिकों की लामबंदी" कहा जाता है - पेरिस में मेयर के घर पर जलती हुई कार से हमला किए जाने के बाद हुआ।
व्यापक आक्रोश को बढ़ावा दे रहा है.
आंतरिक मंत्रालय ने देश भर में 45,000 तैनात किए हैं।
सोमवार को पुलिस ने कुल 157 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया.

यूक्रेन का दावा है कि उसने 'मुश्किल' मुकाबले के बाद दक्षिण और पूर्व में बढ़त हासिल की है।

मोंड्यू पर यूक्रेन ने पिछले हफ्ते मुश्किल स्थिति में दक्षिण और पूर्व में बढ़त हासिल करने की सूचना दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जवाबी हमले की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के 158 किमी 2 क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है।
हालाँकि कीव ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से अधिक सैन्य सहायता के लिए आग्रह किया है।
यूक्रेनी प्रधान मंत्री ज़ेलास्ले ने कहा, "पिछला सप्ताह अग्रिम पंक्ति पर कठिन था लेकिन हम प्रगति कर रहे हैं"
रूसी एफएसबी
रूस की सुरक्षा सेवा ने कहा कि उसने क्रीमिया के प्रमुख की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया है।
शोइगू की टिप्पणी
रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगस ने बताया कि रूसी सेना ने जर्मनी, पोलैंड और पुर्तगाल से खरीदे गए सभी लेपर्ड टैंक को नष्ट कर दिया है।

चीन श्रीलंका के क्रेडिटोस प्लेटफॉर्म से बाहर रहेगा।

चीन श्रीलंका के लिए सामान्य ऋण उपचार योजना पर बातचीत करने वाले आधिकारिक ऋणदाता मंच में "शामिल नहीं होगा"। लेकिन श्रीलंका के रक्षा मंत्री ने कहा कि वह बीजिंग के द्विपक्षीय समर्थन को लेकर आश्वस्त हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा.
आधिकारिक ऋणदाता समिति
इसका गठन श्रीलंका के ऋण उपचार के अनुरोध के बाद किया गया है। 17 देश इसका हिस्सा हैं.
इसकी सह-अध्यक्षता भारत, जापान और फ्रांस द्वारा की जाती है, चीन ने इसमें एक निरीक्षण के रूप में भाग लिया है, श्रीलंका सितंबर की समय सीमा से पहले अपने विदेशी और घरेलू ऋण दोनों के पुनर्गठन के लिए समय के साथ दौड़ रहा है।

सम्पादकीय-1

मोके और दर्पण

अजित पवार और मंत्री शिंदे गुट के साथ बीजेपी के लिए बढ़ा सकते हैं तनाव!

संपादकीय किस बारे में है?

संपादकीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता अजित पवार द्वारा पार्टी को विभाजित करने के बारे में है। इसमें बीजेपी-एनसीपी-शिवसेना और एनसीपी दोनों के लिए नई चुनौतियों की बात की गई है.

अजित पवार और उनके एनसीपी से अलग होने के बारे में

रविवार को अजित पवार अपने चाचा और राकांपा के संरक्षक शरद पवार से अलग हो गए।
फिलहाल एनसीपी के पास 58 विधायक हैं
2019 महाराष्ट्र विधानसभा की सीटें
कुल सीटें- 288

बीजेपी	शिवसेना	शिवसेना (यूबीटी)	एनसीपी	कांग्रेस
↓	↓	↓	↓	↓
105	40	16	56	44

अजित पवार ने अलग होते हुए कहा है कि एनसीपी के सभी विधायक उनकी तरफ से हैं.
2019 में भाजपा के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के नेतृत्व में बनी सरकार में अजित पवार अल्प अवधि के लिए डिप्टी सीएम थे।
बाद में महा विकास अघावड़ी (कांग्रेस+एनसीपी)+शिवसेना) सत्ता में आई।
2022 में एकनाथ शिंदे 56 में से 40 विधायक लेकर टूट गए। उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पीकर को एकराथ शिंदे के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करनी होगी। जल्द ही एकराथ शिंदे से छिन सकता है सीएम पद! और संभावना है कि अजित पवार को महाराष्ट्र का नया सीएम बनाया जाए.
अजित पवार अवश्य ही इस अवसरवादिता से खेल रहे होंगे।
एनसीपी के मातृ गुट ने अलग हुए विधायकों और अजित पवार के लिए अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर दी है।
बीजेपी की दुविधा के बारे में
बीजेपी ने पहले एनसीपी और उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। भाजपा के विभिन्न नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, ये वैचारिक मतभेद एकनाथ के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना के बीच नई लड़ाई शुरू कर सकते हैं।

सम्पादकीय-2

पानी साफ़ करना

भारत को पोर्टेबल पानी पहुंचाने की योजना को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए।

संपादकीय किस बारे में है?

संपादकीय में भारत में नल जल प्रणाली "हर घर जल" योजना की प्रगति पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है।

"हर घर जल" योजना के बारे में।

यह जल शक्ति मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार (लगभग 25 करोड़) को नल के पानी के कनेक्शन से जोड़ना है।
नल जल कनेक्शन जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर नल जल उपलब्ध कराता है।
योजना की प्रगति

"हर घर जल" मिशन की प्रगति।

2019 में शुरू किए गए कार्यक्रम का उद्देश्य अप्रैल 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को नल के पानी से जोड़ना था।
जब यह शुरू हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 16% के पास नल का पानी कनेक्शन था जो बढ़कर 64% हो गया है।
उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2024 तक 19.5 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंच जाएगा।
राज्यों द्वारा केवल 1,681 15% गांवों को "हर घर जल" के रूप में रिपोर्ट किया गया है और केवल 54,000 को 'प्रमाणित' किया गया है, इसका मतलब है कि उनकी ग्राम पंचायत ने औपचारिक रूप से अनुपालन स्वीकार कर लिया है।
गुजरात, हरियाणा, पंजाब आठ बड़े राज्यों में से हैं जो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। केंद्र को इसमें तेजी लाकर देनी चाहिए

विज्ञान

दिल्ली अध्यादेश की वैधता

अध्यादेश के बारे में.

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कार्यकारी अधिकारियों के स्थानांतरण और भर्ती की शक्ति होगी।
सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसके द्वारा ऐसी शक्ति अंततः राज्यपाल को स्थानांतरित कर दी गई है। राज्यपाल अभी भी राज्य सरकार का निर्णय ले सकते हैं।

प्रश्न :- क्या विधायिका के पास SC निर्णय को टालने और नया कानून बनाने की शक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि चूंकि संसद के पास न्यायिक शक्तियां नहीं हैं, इसलिए वह फैसले का आधार बदले बिना अदालत के फैसले को खारिज नहीं कर सकती। अध्यादेश संवैधानिक आधार नहीं देता.

अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) बनाम जीएनसीटीओ अधिनियम (1991)।

अनुच्छेद 239 एए (3) (ए)
इसमें कहा गया है कि दिल्ली की विधान सभा के पास हाथ, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाने की सभी शक्तियां होंगी।
जीएनसीटीडी अधिनियम (1999)
यह बताता है

SCIENCE